印地语时文

第二册

孙卫国　编

中国人民解放军外国语学院
一九九四年十一月

आपातकाल और उसके बाद

२७ जून की रात को राष्ट्र के नाम एक प्रसारण में मैंने आपातस्थिति लागू करने के कारण दिए थे:

हिंसा और घृणा का एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया है, जिसके फलस्वरूप एक केबिनट मंत्री की हत्या हो गई तथा मुख्य-न्यायाधीश के प्राण लेने की कोशिश की गई। विरोधी दलों ने केन्द्र शासन को पूरी तरह पंगु बना देने के लिए घेराव, आन्दोलन, तोड़-फोड़ और औद्योगिक कामगारों, पुलिस तथा सुरक्षा सेनाओं को भड़काने का एक कार्यक्रम बनाया था। इनमें से एक तो इस सीमा तक पहुंच गए थे कि वे कहने लगे थे-- सशस्त्र सेनाएं उन आदेशों का, जिन्हें वे गलत समझती हैं, पालन न करें। यह कार्यक्रम इसी मास २९ तारीख से शुरू होने वाला था। हमें इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बनता और अर्थव्यवस्था को इतना क्षतिग्रस्त करता कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। इसे रोकना ज़रूरी था। विरोधी समूह के कुछ लोगों ने जो कार्यक्रम बनाया, वह लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। वह हरेक कसौटी पर राष्ट्रविरोधी ही सिद्ध होता है और इसकी

अनुमति नहीं दी जा सकती ।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद गुजरात में आंशिक हड़ताल और छोटी-छोटी घटनाओं को छोड़कर, सारा देश सामान्य अवस्था की ओर लौट आया है । सामान्य अवस्था की इस भावना को बनाए रखना आवश्यक है और इस बात का भी ध्यान है कि लोकतंत्र में भी कुछ सीमाएं होती हैं, जिन्हें लांघा नहीं जा सकता । हिंसात्मक कार्य और अर्थहीन सत्याग्रह वर्षों के श्रम और आशा के साथ निर्मित समूचे ढांचे को ढहा देंगे । मुझे विश्वास है कि आपातस्थिति को शीघ्र ही उठाना संभव होगा । आप जानते हैं कि मैंने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमेशा विश्वास किया है । मुझे अभी भी अ उसपर विश्वास है, पर सभी तरह की स्वतंत्रताओं की तरह इस स्वतंत्रता का भी ज़िम्मेदारी और संयम के साथ उपयोग किया जाना चाहिए । आंतरिक गड़बड़ियों की स्थिति में, चाहे वह भाषा को लेकर हुई हों या साम्प्रदायिक दंगों के कारण हुई हों, उसमें गैर-ज़िम्मेदाराना लेखन ने गंभीर शरारतपूर्ण कार्य किया है । हमें ऐसी स्थितियों को रोकना है, क्योंकि अनेक समाचार पत्रों ने कई बार समाचारों को जानबूझ कर तोड़ा-मरोड़ा है और द्वेषपूर्ण तथा उत्तेजक टिप्पणियां

भी की हैं । शांति और स्थिरता की स्थिति लाना ही हमारा उद्देश्य है । सेंसरशिप का उद्देश्य विश्वास का वातावरण पैदा करना है । आल इंडिया रेडियो और अखबारों से सही समाचारों के मिलने में विलंब हुआ है । सभी आवश्यक कानूनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं करने में समय लगता है ।

इस बीच अफवाहें फैलाने वालों और असामाजिक तत्वों की बन आई और उन्होंने हर तरह की कहानियां गढ़कर फैलाईं । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि गिरफ्तार नेताओं के साथ सहानुभूति और सौजन्यता बरती जा रही है ।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और नये कड़े नियंत्रणों के शीघ्र लागू किए जाने की बेसिरपैर की खबरें उड़ाई जा रही हैं । हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है ।

हमारा उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है । इससे ज्यादा रोज़गार मिलेंगे और बेहतर वितरण होगा ।एक तात्कालिक आवश्यकता कृषि और उद्योगों को बिजली पहुंचाने की है । आज सुबह मैं भारत सरकार के सचिवों से मिली थी । मैंने उन्हें प्रशासन को ज्यादा सतर्क बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है ताकि काम अधिक शीघ्रता और अधिक कुशलता से हो सके ।

४६०

यह एकता और अनुशासन का समय है। मुझे विश्वास है कि हर आने वाले दिन के साथ हालत सुधरती जाएगी और इस कार्य में शहरों और गांवों की हमारी जनता हमें पूरा सहयोग देगी, ताकि देश को मजबूत बनाया जा सके।

"७ नवम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने १९७१ के आपके चुनाव को वैध घोषित किया। १४ नवम्बर को विरोधी नेता जयप्रकाश नारायण रिहा कर दिए गए। पर ८ दिसम्बर को भारतीय प्रेस पर नियंत्रण पर्याप्त कड़े कर दिए गए और २३ दिसम्बर को मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया गया। एक शक्तिशाली व्यक्ति ने रक्षा मंत्रालय का भार संभाला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चंडीगढ़ में हुए ७५ वें अधिवेशन में अनेक कड़े उपाय अपनाने का निश्चय किया गया जिनमें आपात स्थिति का स्थगन, चुनावों का स्थगन तथा संविधान का पुनरीक्षण भी सम्मिलित था। इसपर समाचार-पत्रों के टिप्पणीकारों ने लिखा था कि—'विश्व के विशाल लोकतन्त्र की मृत्यु हो गई।' उसी समय यह घोषणा की गई कि कांग्रेस दल का पुनर्गठन किया जाएगा।

५ जनवरी को विरोध पक्ष ने संसद के उद्घाटन सत्र का बहिष्कार किया। मार्च, १९७१ में निर्वाचित सा लोकसभा ने

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

निर्णय किया और इसका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया ।

२ जुलाई को संयुक्त राज्य अमरीका के परमाणु निभंत्रण आयोग ने भारत को यूरेनियम भेजने का निर्णय किया । जुलाई में ही नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों की संवाद-समितियों का एक 'पूल' बनाने का निश्चय किया गया ।

१६ से २३ अगस्त तक आपने कोलम्बो में गुटनिरपेक्ष देशों के पांचवें शिखर सम्मेलन में भाग लिया । वहां आपके भाषण का मुख्य स्वर था-- "स्वाधीनता से आत्मनिर्भरता की ओर ।"

१६ अगस्त को संसद ने निवारक नज़रबंदी अधिनियम को बढ़ाने की सम्मति प्रदान की । १८ सितम्बर को सरकार द्वारा विदेशी पत्रकारों पर लगाई गई सेंसरशिप उठा ली गई, लेकिन भारतीय पत्रकारों पर नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया । ४ अक्तूबर को दिल्ली में मज़दूर नेता जार्ज फर्नांडीस तथा अन्य २० व्यक्तियों पर मुकदमा शुरू हुआ और १७ अक्तूबर को 'पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज़ एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट' की नई दिल्ली में स्थापना हुई । इसी समय १० से १७ अक्तूबर

के बीच आप मारीशस, तंजानिया और जाम्बिया गईं, जहां आपने दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति आन्दोलनों को भारत के समर्थन की घोषणा की । भारत को तीसरे विश्व के प्रमुख नेताओं का समर्थन मिला । इसी समय विश्व बैंक ने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आपात स्थिति के बाद हुए आर्थिक तथा वित्तीय सुधारों पर प्रकाश डाला । ³¹

कड़े उपाय अपनाने के कारण ही हम अर्थव्यवस्था को फिर से सामान स्तर पर ला सके थे । हमारा कृषि-उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, हमारा निर्यात, ये सब एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गए थे । हम तस्करी, जमाखोरी और ऐसी बहुत-सी चीज़ों को रोकने में समर्थ हो सके, जो किसी के व्यक्तिगत हित के लिए तो बुरी नहीं थी, लेकिन जिनसे देश की अर्थव्यवस्था, खासकर गरीब जनता और कम आय वाले मध्यमवर्ग के लोगों पर बुरा असर पड़ता था । इन उपायों, जैसे तस्करी पर रोक-आदि, के कारण हम विदेशी मुद्रा कमाने में भी समर्थ हो सके । पहली बार हमारे भुगतान का संतुलन आश्चर्यजनक रूप से संतोषप्रद था ।

इस दौरान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के

ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्य अर्थशास्त्री भी भारत आए। इतने थोड़े समय में हमने जो हासिल किया, उससे वे आश्चर्य में पड़ गए। यही नहीं, इसी छोटी अवधि में हमने शहरों में सफाई ला दी थी, भिखारियों को हटा दिया था और अनुशासन लागू करने में सफल हुए थे। व्यापारियों पर भी थोड़ा बहुत अनुशासन लागू किया गया था, पर छात्रों व अन्य लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन अनुशासन की हवा का उन पर भी असर हुआ। इसके फलस्वरूप परीक्षाएं भी समय पर हुईं और जैसा कि ज्ञान के केन्द्रों का काम चलना चाहिए, विश्वविद्यालयों का काम भी शांतिपूर्ण ढंग से चला।

"नवम्बर में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की आलोचक बन गई। यों सी० पी० आई० सन् १९६७ से आपका समर्थन करती आ रही थी। दल के विभाजन की प्रक्रिया के दौरान जब आपने पुराने नेताओं को सत्तारूढ़ कांग्रेस दल से निकाल बाहर किया तो सी० पी० आई० ने उस समय भी आपका समर्थन किया। पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, सी० पी० आई० की चिंता बढ़ती

गई । सी० पी० आई० आपकी दक्षिण पंथी प्रतीत होने वाली आर्थिक नीतियों के कारण चिंतित थी । निजी उद्योगों को दी गई रियायतों, मज़दूरों को अनिवार्य बोनस भुगतान की समाप्ति और यूनियनों की गतिविधियों में कटौती ने सी० पी० आई० को उलझन में डाल दिया था । सी० पी० आई० आपके पुत्र को लेकर भी परेशान थी, क्योंकि उनकी नीतियां स्पष्ट रूप से सिद्धांतों से परे, विघ्नकारी (हठवादी) व घोर रूप से कम्युनिस्ट विरोधी थीं । सी० पी० आई० ने सामाजिक सुधार के आपके बीस सूत्री कार्यक्रम का तो समर्थन किया, पर उसने संजय के पांच सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करने से साफ-साफ मना कर दिया । पर मास्को ज़रा-सी बात पर भारत के साथ अपने विशेष सम्बन्धों को नष्ट नहीं होने देना चाहता था। सन् १९७१ से उसकी भारत के साथ शांति, मित्रता एवं सहयोग की बीस वर्षीय संधि अमल में है ।

२५ दिसम्बर को आपने पिछले कई वर्षों में पहली बार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की कड़ी भर्त्सना की ।"

मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कड़ी भर्त्सना नहीं की । मैं

तो केवल एक ऐतिहासिक परिदृश्य को सामने रखना चाहती थी। मैंने कहीं बाहर नहीं कहा था, सिर्फ अपने ही कार्यकर्ताओं के एक प्रशिक्षण-शिविर में यह सब कहा था। मैं यह कहना चाहती थी कि हालांकि कम्युनिस्टों ने हमारे कार्यक्रम का, जिन्हें वे प्रगतिशील समझते थे, समर्थन किया, पर उनका न केवल मेरे, बल्कि मेरे पिता के बारे में भी पूरी तरह विरोधी दृष्टिकोण था। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं उनकी आलोचना भी नहीं करना चाहती थी। मैं तो केवल विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या है, यही दिखाना चाहती थी, खासकर इसलिए कि लोगों ने उनके बारे में सवाल पूछे थे कि क्या बात है कि वे (कम्युनिस्ट) कल तक हमारे साथ थे और आज आलोचक बन गए हैं ? मैं इसीलिए सारी बातें सामने लाना चाहती थी। कुछ गलतफहमी हो गई थी। हमारे कुछ तथाकथित वामपंथियों ने कम्युनिस्ट पार्टी को एक खास ब्यौरा बताया और उन्होंने उसे मान लिया। दर-असल सी० पी० आई० ने तब हमसे लड़ाई करने की ठान ली थी। यदि वे सही मायनों में सच्चा सहयोग चाहते होते तो हम मिल-बैठकर मसलों का निपटारा कर लेते। वे मुझसे मिलने ज़रूर आए। शायद वे दो बार आए, पर वे

मुझसे लड़ने की भावना से ही आए थे। बजाय इसके कि वे मेरे साथ बैठते, समस्या कैसे हल की जाए इसपर विचार करने की कोशिश करते, उन्होंने मुझ पर चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया।

पांच सूत्री कार्यक्रम के प्रति सी० पी० आई० का रुख क्या है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह पांच-सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस ने नहीं बनाया था बल्कि यह तो आजादी के बाद से ही हमारा योजनाबद्ध कार्यक्रम था--परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, शहरों की स्वच्छता, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष, ये सब बातें तो शुरू से ही हमारे कार्यक्रम का हिस्सा थीं। यह जरूर है कि युवा कांग्रेस ने इन कामों को अपने हाथ में लिया था। युवा कांग्रेस के लोगों का विश्वास था कि इन बातों में लोगों की निजी दिलचस्पी होगी। भूमि-सुधार एक अच्छा कार्यक्रम है, पर एक नागरिक उसकेब बारे में कुछ नहीं कर सकता। यह तो सरकार का काम है। यही बात कर्जों से राहत देने के बारे में भी है।

२० सूत्री कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम है। पार्टी ज्यादा से ज्यादा यही देख सकती है कि उसपर ठीक से अमल किया

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

जाए । इसकी बनिस्बत पांच सूत्री कार्यक्रम लोगों की निजी समस्याओं से ज्यादा जुड़ा है । उदाहरण के लिए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को यही वायदा करना था कि मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं जाति प्रथा से लड़ूगा, मैं पेड़ लगाऊंगा, पेड़ न कटने पाएं इस बात का ध्यान रखूंगा । आप इस कार्यक्रम को देखें, उसमें किस बात पर एतराज़ किया जा सकता है । क्या आप कह सकते हैं कि शहरों को साफ नहीं रखा जाना चाहिए ? या दहेज जैसे बर्बर रिवाज़ या छुआछूत की बुराई जारी रहने दी जाए ?

संजय ने ज़रूर कुछ कम्युनिस्ट विरोधी बातें कहीं । पर उसने कम्युनिज्म पर हमला नहीं किया । अब ऐसी समस्याओं से निपटने का यही तरीका हो सकता है कि साथ बैठा जाए और उसे बताया जाए कि उसे गलतफहमी हुई है । पर ऐसा करने की बजाय कम्युनिस्टों ने उसपर पूरे ज़ोर-शोर से हमला कर दिया । अतः उसका एक या दो बार फिर अपनी राय ज़ाहिर करना स्वाभाविक ही था । मेरे ख्याल में उसने कुल मिलाकर केवल तीन बार ये बातें कही थीं ।

चूंकि कांग्रेस और युवा कांग्रेस द्वारा धन इकट्ठा करने के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थीं इसलिए संजय ने

एक टिप्पणी की थी । लोगों का कहना था कि वे नहीं जानते कि पैसा कहां जा रहा है इसलिए संजय ने एक आम सभा में कहा, " जब तक किसी के पास अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या किसी और प्रकार का अधिकार न हो, उसे पैसा न दो । यदि पैसा दो भी तो " क्रास्ड चेक" द्वारा दो और उसकी रसीद लो ।" बहुत से लोगों को चंदा इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था और वे अनकली तौर पर उसे इकट्ठा कर रहे थे । इसलिए सभी लोग चाहते थे कि स्थिति स्पष्ट कर दी जाए ! इसीलिए संजय ने वह एक सामान्य सी टिप्पणी की थी । पर कुछ लोगों ने उसे अपने लिए समझा और नाराज़ हो गए ।

मैंने जब किसी भड़कावे के बारे में सुना तो फौरन उसके विरूद्ध कहा है, पर किसी और ने उसपर बोलने की ज़रूरत नहीं समझी। यदि कोई मुझपर हमला करता तो मेरे समर्थन के लिए भी लोग नहीं आते थे । दरअसल, उन्होंने कभी भी ऐसा दिली तौर पर समर्थन नहीं किया । जब भी किसी और पर हमला होता, तो वे चुप रहते । मिसाल के तौर पर, जब संसद में ललित नारायण मिश्र पर हमला किया गया तो पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया और जब मैंने उनका समर्थन किया तो उन्होंने कहा, "आप

बेवकूफ हैं, आप उनका समर्थन क्यों कर रही हैं । इससे आप जनता में अलोकप्रिय हो जाएंगी ।- मैंने कहा:" देखिए, वे हमारे साथी हैं । यदि आप सोचते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है, तो वे उनपर मुकदमा चला सकते हैं, पर मुझे उनपर लगाए गए आरोपों पर विश्वास नहीं है । इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने गलत काम किए हैं ।" और, बाद में यह साबित भी हो गया कि उन्होंने गलत काम नहीं किया था ।

देश में फैली अस्थिरता और अनुशासनहीनता ही आपातस्थिति लगाने और चुनावों को स्थगित करने का कारण थी । हमने हालात पर काबू पा लिया । इसलिए मैंने सोचा कि अब चुनाव कराने चाहिए ।

अपनी जीत पर मुझे पक्का यकीन नहीं था । मुझे यकीन था कि हमें कोई बहुत बड़ा बहुमत नहीं मिलेगा । मैं सोचती थी कि शायद हम किसी तरह जीत जाएंगे । दरअसल, मैंने हार-जीत के बारे में कभी सोचा नहीं था । मैंने केवल यही सोचा था कि हमने किसी कारणवश चुनाव स्थगित किए थे और अब चूंकि वह कारण खत्म हो गया है, हमें चुनाव कराना चाहिए ।

सही बात यही है। यह पूरे तौर पर एक लोकतांत्रिक कार्य था।

हर एक आदमी विरोधी दलों को ही लोकतंत्र बनाए रखने का श्रेय देता है, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने ही चुनावों के बारे में फैसला किया। मैंने बड़े अनुभव से अपनी हार मान ली थी और विरोधी पक्ष को अपने सहयोग का विश्वास भी दिलाया था, लेकिन वे लोग तो कांग्रेस को नष्ट करने पर तुले हुए थे।

इस बात को कहने में कोई फायदा नहीं कि हमने लोगों को गिरफ्तार किया था। हमने एक अलग संदर्भ में ये गिरफ्तारियां की थीं। उस समय आन्दोलन का खतरा था और देश की अर्थव्यवस्था चरमराकर ढहने को थी। आपातस्थिति के बाद जब हमने विरोधियों के हाथों सत्ता सौंपी, तब अनाज के गोदाम लबालब भरे हुए थे और देश में हर तरह स्थिरता थी।

आपात स्थिति के दौरान हमने आर्थिक सुधार के अलावा राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत कुछ पाया था। आजादी के पहले या बाद में भारत की एकता कभी इतनी अखण्ड और अर्थवान नहीं, जितनी कि आपातस्थिति के दौरान थी। खास तौर पर हम सीमावर्ती प्रदेशों के लोगों को राष्ट्रीयता की मुख्य धारा से जोड़ने में सफल हो सके थे। दुर्भाग्य से अब

इस एकता में दरारें पड़ चुकी हैं और प्रत्येक राज्य में कठिनाइयों का दौर-दौरा है ।

"जून १९७५ में घोषित आपातस्थिति के अन्तर्गत लागू कुछ उपायों को आपने २० जनवरी, १९७७ को हटा लेने का निर्णय किया, तथापि आपातस्थिति बरकरार रही । अनेक राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए गए और सेंसरशिप भी उठा ली गई । संसद के हेमन्त-सत्र में पारित नया संविधान आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही तैयार किया गया था । उससे आपको अधिक अधिकार मिल गए थे ।

१३ मास के कारावास के बाद मुक्त होने पर मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी नाम से एक संयुक्त मोर्चे के गठन की घोषणा की । इसमें जनसंघ, कांग्रेस का असंतुष्ट वर्ग (कांग्रेस अर्स), इंडियन पीपुल्स पार्टी और समाजवादी पार्टी शामिल थीं ।

२ फरवरी का कृषिमन्त्री श्री जगजीवन राम ने कांग्रेस और सरकार दोनों से त्यागपत्र दे दिया । भारतीय राजनीतिक जीवन के प्रथम श्रेणी के नेताओं में से वे एक थे और जून १९७५ में आपातस्थिति की घोषणा तक, जबकि पुराने नेताओं का नियंत्रण बना हुआ था, वे एक " शक्तिसम्पन्न व्यक्ति

समझे जाते थे। संसद में जगजीवनराम, भारत की आबादी के सातवें हिस्से, अछूतों के एक सर्वाधिक प्रमुख प्रवक्ता थे।

श्री जगजीवन राम के बहिर्गमन से सत्तारूढ़ दल में एक सच्चा और नया विभाजन हुआ था। पिछला विभाजन १९६९ में हुआ था। श्री जगजीवन राम ने एक नयी पार्टी--कांग्रेस फार डेमोक्रेसी -- के गठन की घोषणा की थी।''

श्री जगजीवन राम कुछ कहना नहीं चाहते थे। उनका तो बस यही ख्याल था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उन्होंने (विरोधी पक्ष के लोगों ने) भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का वायदा किया था।

लोग मुझे बहुत पहले से बताते आ रहे थे कि श्री जगजीवन राम आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं और कुछ करने वाले हैं। मैं भी जानती थी कि वे कुछ करेंगे पर मुझे यह नहीं मालूम था कि वे कब और किस तरह कदम उठाएंगे। मैं यह भी जानती थी कि उन्हें सरकार से अलग कर देने से कोई फायदा नहीं होगा।

दल और सरकार छोड़ने के एक दिन पहले वे मेरे पास आए

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com